

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राजस्थान)**

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 1442/2018

दायरा तिथि : 01.10.2018

फैसला तिथि : 28-5-2019

प्रार्थीगण:-

1. श्रीमति अम्बादेवी पुत्री स्व. हिमताजी
  2. श्रीमति लक्ष्मीदेवी पुत्री स्व. हिमताजी
  3. श्रीमति भंवरीदेवी पुत्री स्व. हिमताजी
- जातिगण रावल ब्राह्मण, निवासीगण-सेवाडी  
तहसील बाली, जिला-पाली (राज.)

ब न अ म

अप्रार्थीगण :-

1. स्व. नन्दकिशोर पुत्र हिमताजी के कायम मुकाम  
1/1 धमेन्द्र कुमार पुत्र स्व. नन्दकिशोरजी  
1/2 जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व. नन्दकिशोरजी  
1/3 राकेश कुमार पुत्र स्व. नन्दकिशोरजी  
1/4 सुभाष कुमार पुत्र स्व. नन्दकिशोरजी  
1/5 दीपक कुमार पुत्र स्व. नन्दकिशोरजी  
1/6 रणजीत कुमार पुत्र स्व. नन्दकिशोरजी  
जातिगण रावल ब्राह्मण, निवासीगण सेवाडी, तहसील बाली
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति:-

1. श्री गणपतलाल चौधरी
  2. श्री भंवरसिंह राजपुरोहित व मूलसिंह यादव
  3. श्री अय्यूव अली
- अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से  
अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं० 1/1  
व 1/4 की ओर से  
अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1/2,  
1/3 व 1/5

--: आदेश ::--

दिनांक: 28-5-2019

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित  
आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी.**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश कर ग्राम सेवाडी तहसील बाली में स्थित निम्न वर्णन की भूमियों में अप्रार्थीगण संख्या-1/1 लगाय 1/6 के नाम दर्ज भूमियों में प्रार्थीगण का बहिस्सा बराबर बताते हुये प्रस्तुत घोषणा खातेदारी एवं सार्वकालिक निषेधाज्ञा के वाद के निर्णय तक वर्णित भूमियों में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा में निहित प्रार्थीगण के हिस्से के संवध में बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। वर्णित भूमि के हाल सैटलमेंट संवत् 2037 के पूर्व का विवरण:-

क्र०सं०	खसरा नंबर	रकबा	नाम खातेदार
1	412	43 बीघा 10 बिस्वा	शंकर छोगा, हिमता पि० परता 1/6 हिस्सा
2	412/2	4 बीघा 16 बिस्वा	
3	565	7 बीघा 14 बिस्वा	
4	566	6 बीघा 10 बिस्वा	
5	567	6 बीघा	
6	567/1	19 बिस्वा	
7	570	14 बीघा 13 बिस्वा	
8	570/1	11 बीघा 08 बिस्वा	
9	412/1	8 बिस्वा	
10	564	9 बिस्वा	
11	568	12 बिस्वा	
12	569	16 बिस्वा	
कुल खसरा-12		97 बीघा 15 बिस्वा	

पेज लगातार-2



न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1442/2018 अनवान अम्बादेवी वगैरा बनाम नन्दकिशोर के का.मु. धमेन्द्र कुमार वगैरा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम, 1955 संप्रति आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी

उक्त वर्णित भूमि के भूभाग से बने हाल खसरा नंबर 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447 रकबा क्रमशः 0.45 हैक्टर, 0.17 हैक्टर, 0.27 हैक्टर, 0.36 हैक्टर, 0.01 हैक्टर, 0.06 हैक्टर, 0.61 हैक्टर, 0.59 हैक्टर, 0.62 हैक्टर, 0.69 हैक्टर, 4.46 हैक्टर कुल खसरा-13 कुल रकबा 7.96 हैक्टर एवं दूसरा खाता जिसके खसरा नंबर 1993 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. वेरा एवं खसरा नंबर 1994 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गै.मु. सडा एवं तीसरा खाता जिसके खसरा नंबर 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 रकबा क्रमशः 0.43 हैक्टर, 0.26 हैक्टर, 0.38 हैक्टर, 0.35 हैक्टर, 0.36 हैक्टर, 0.27 हैक्टर, 0.25 हैक्टर, 0.46 हैक्टर, 0.50 हैक्टर, 0.15 हैक्टर, 0.30 हैक्टर, 0.20 हैक्टर, 0.70 हैक्टर, 0.28 हैक्टर, 0.81 हैक्टर, 0.36 हैक्टर 0.41 हैक्टर, 0.43 हैक्टर, 0.17 हैक्टर, 0.14 हैक्टर, 0.23 हैक्टर, 0.26 हैक्टर कुल खसरा-22 कुल रकबा 7.70 हैक्टर इन तीनों खातों की भूमियों के 1/6 हिस्सा में दर्ज नन्दकिशोर पुत्र हिमता के संबंध में प्रस्तुत घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा के बाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि अप्रार्थी रिकॉर्ड में दर्ज 1/6 हिस्सा का वेचान, हस्तान्तरण नहीं करे तथा रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सेवाडी तहसील वाली के गत् खसरा नंबर 412 रकबा 43 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 412/2 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 565 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 566 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 567 रकबा 6 बीघा, खसरा नंबर 567/1 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 570 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 570/1 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 412/1 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 564 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 568 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 569 रकबा 16 बिस्वा कुल खसरा 12 कुल रकबा 97 बीघा 15 बिस्वा सैटलमेंट पुर्व के अधिकार अभिलेख जमावंदी संवत् 2037 से पुर्व में 1/6 हिस्सा में शंकर, छोगा व हिमता पि० प्रताप दर्ज थी। छोगाजी उर्फ अलकुजी व शंकरजी की मृत्यु लाओलाद होने से उनके जीवित भाई हिमताजी पुत्र प्रतापजी के नाम दर्ज हुई तथा भूप्रबन्ध के बाद तैयार नये अधिकार अभिलेखों में ग्राम सेवाडी के पुराने खसरा नंबर 412 रकबा 43 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 412/2 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 565 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 566 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 567 रकबा 6 बीघा, खसरा नंबर 567/1 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 570 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 570/1 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 412/1 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 564 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 568 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 569 रकबा 16 बिस्वा कुल खसरा 12 कुल रकबा 97 बीघा 15 बिस्वा के भूभाग से कायम हाल खसरा नंबर 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447 रकबा क्रमशः 0.45 हैक्टर, 0.17 हैक्टर, 0.27 हैक्टर, 0.36 हैक्टर, 0.01 हैक्टर, 0.06 हैक्टर, 0.61 हैक्टर, 0.59 हैक्टर, 0.62 हैक्टर, 0.69 हैक्टर, 4.46 हैक्टर कुल खसरा-13 कुल रकबा 7.96 हैक्टर एवं दूसरा खाता जिसके खसरा नंबर 1993 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. वेरा एवं खसरा नंबर 1994 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गै.मु. सडा एवं तीसरा खाता जिसके खसरा नंबर 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 रकबा क्रमशः 0.43 हैक्टर, 0.26 हैक्टर, 0.38 हैक्टर, 0.35 हैक्टर, 0.36 हैक्टर, 0.27 हैक्टर, 0.25 हैक्टर, 0.46 हैक्टर, 0.50 हैक्टर, 0.15 हैक्टर, 0.30 हैक्टर, 0.20 हैक्टर, 0.70 हैक्टर, 0.28 हैक्टर, 0.81 हैक्टर, 0.36 हैक्टर 0.41 हैक्टर, 0.43 हैक्टर, 0.17 हैक्टर, 0.14 हैक्टर, 0.23 हैक्टर, 0.26 हैक्टर कुल खसरा-22 कुल रकबा 7.70 हैक्टर इन तीनों खातों की भूमियों के 1/6 हिस्सा में शंकर, छोगा व हिमता पि. प्रताप की जगह नन्दकिशोर पुत्र हिमता दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि स्व० हिमता की स्व. अर्जित नहीं होकर पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि होते हुये वादग्रस्त भूमि के 1/6 हिस्सा में स्व० हिमता पुत्र प्रताप के निहित हिस्सा में प्रार्थीगण जो कि स्व० हिमता की पुत्रिया है तथा अप्रार्थी संख्या-01 जो कि स्व. हिमता का पुत्र है, वहिस्सा बराबर के हकदार थे। परन्तु अप्रार्थी संख्या-01 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर वादग्रस्त भूमियों के 1/6 हिस्सा में अकेले का नाम दर्ज करवा दिया। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या-01 आपस में भाई बहिन होने से तथा आपस में मधुर संबंध होने से प्रार्थीगण ने कभी राजस्व रिकॉर्ड नहीं देखा। इस वर्ष रक्षा बंधन पर जब पेज लगातार-3



39 - खण्ड अधिकारी, वाली

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1442/2018 अनवान अम्बादेवी वगैरा बनाम नन्दकिशोर  
के का.मु. धमेन्द्र कुमार वगैरा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955  
सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी

प्रार्थीगण अपने पैतृक पुश्तैनी घर पर गई तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि पर जाने से रोकना एवं वहाँ की पैदावार मुग वगैरा नहीं देने की बात की। इस पर प्रार्थीगण ने राजस्व रेकर्ड की जांच की एवं नकले प्राप्त की तो प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि अप्रार्थी संख्या-01 ने बाले-बाले प्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि में अपने अकेले का संपुर्ण 1/6 हिस्से में नाम दर्ज करवा दिया। तथा रेकर्ड में नाम दर्ज होने से अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगाय 1/6 प्रार्थीगण को खातेदार मानने से इन्कार हो गये और वादग्रस्त कृषि भूमि पर जाने से रोकने लगे। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को उनकी गैर कानूनी हरकतों से रोकना तो अप्रार्थी संख्या 1/1 ने धमकी दी कि वह वादग्रस्त भूमि का वेचान कर देगा। जिससे प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता की पैतृक पुश्तैनी भूमि के 1/6 हिस्सा में बहिस्सा बराबर की खातेदार होने से घोषणा खातेदारी के वाद के साथ सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। जो वाद प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। वाद के निस्तारण में समय लगेगा एवं इस दौरान यदि अप्रार्थीगण रेकर्ड में दर्ज त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण कर देते हैं तो प्रस्तुत वाद एवं उक्त प्रार्थना पत्र का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। अतः प्रस्तुत वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपी चालू जमावंदी संवत् 2072 से 2078, फोटो प्रति जमावंदी संवत् 2052 से 2055, भू० प्रबन्ध संवत् 2017 की खतौनी बन्दोवस्त की फोटो प्रति, जमावंदी प्रमाणित प्रतिलिपी संवत् 2027 से 2030, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपी, प्रमाणित प्रतिलिपी खतौनी बन्दोवस्त संवत् 2037 से 2056 पेश किये गये। तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में प्रार्थीया अम्बादेवी का शपथ पत्र भी पेश किया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1/2 जितेन्द्रकुमार, 1/3 राकेशकुमार, 1/5 दीपककुमार ने अपने अधिवक्ता श्री अय्युव अली सैयद के माध्यम से इकबालिया जवाब पेश किया गया। अपने जवाब में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से सहमति व्यक्त करते हुये वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व० हिमताजी से प्राप्त होने तथा स्व० हिमताजी द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि में निहित 1/6 हिस्सा अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व० नन्दकिशोरजी अथवा अन्य किसी के पक्ष में किसी प्रकार की वसीयत नहीं करने से हिन्दु उत्तराधिकारिता के प्रावधानों अनुसार वादग्रस्त आराजी में स्व० नन्दकिशोर के साथ प्रार्थीगण बहिस्सा बराबर की खातेदार थी। परन्तु हिमताजी के स्वर्गवास के बाद अकेले नन्दकिशोर का नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थीगण का कानूनन स्व. नन्दकिशोर के साथ बराबर हिस्से के खातेदारी अधिकार बनते है। वादग्रस्त आराजी में कानूनन हिमताजी के फुट स्टेप्स में प्रार्थीगण को भी अधिकार है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं है जिससे कानूनन वादग्रस्त आराजी को प्रोटेक्ट किया जाना आवश्यक है। जवाब के अन्त में निवेदन किया कि पक्षकारान् के मध्य अनावश्यक मुदकमेवाजी न हो व मौके पर शान्ती बनी रहे, इसके लिये प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रोटेक्ट किये जाने का आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र का अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/4 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों से असहमति जताते हुये प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं का पैरावार निम्नानुसार जवाब पेश किया :-

1. कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड में दर्ज सभी खातेदारान् को पक्षकार नहीं बनाया है जिससे प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना-पत्र चलने योग्य नहीं है।
2. प्रार्थीगण ने रेकर्ड में दर्ज सभी सहखातेदारान् को पक्षकार नहीं बनाया तथा न्यायालय को गुमराह कर बिना नोटिस एक तरफा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी कराया है जो काबिल खारिज के है। हिमताजी की मृत्यु सन् 1965 के लगभग होना सही है। प्रार्थीगण 1 लगाय 3 शादीशुदा है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत नियमानुसार हिमताजी के एकमात्र Male son नन्दकिशोर ही होने से एवं वाद में वर्णित कुल खसराजात की कुल भूमि, जो पैतृक थी, हिमताजी का 1/6 हिस्सा बहैसियत खातेदारी कब्जे काश्त का उनके जीवनकाल में रहा एवं हिमताजी की मृत्यु के बाद बहैसियत खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण के पिता नन्दकिशोर का कब्जा काश्त शान्तिपूर्ण रहा। अप्रार्थीगण के पिता नन्दकिशोरजी की मृत्यु के बाद नन्दकिशोरजी के वारिस उत्तराधिकारी अप्रार्थीगण 1 लगाय 6 का बहैसियत खातेदार काश्तकार कब्जा काश्त

पेज लगातार—4



अप - अन्तर्गामी, बाली

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1442/2018 अनवान अम्बादेवी वगैरा बनाम नन्दकिशोर  
के का.मु. घग्नेन्द्र कुमार वगैरा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955  
सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी

शान्तिपूर्वक प्रार्थीगण की जानकारी में चला आ रहा है, यानि हिमताजी अप्रार्थीगण के दादा की मृत्यु के बाद 54 वर्षों में शान्तिपूर्वक हिमताजी के पुत्र नन्दकिशोर व नन्दकिशोर की मृत्यु के बाद नन्दकिशोर के पुत्र अप्रार्थीगण का बहैसियत खातेदार काश्तकार अन्य सहखातेदारान के साथ शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त कृषि भूमि में हिमताजी के वारिसान प्रार्थीगण का नाम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के तहत व्यक्तिगत विधि के तहत दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत नहीं होने से एवं राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों से मिलावट करने के तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वाद एवं प्रार्थना-पत्र में वर्णित खसराजात की भूमि को-पार्सनरी सम्पत्ति है, जिसमें पुत्रियों को पुत्र के समान हिस्सा हक देने का प्रावधान ही नहीं था। वादग्रस्त भूमि को-पार्सनरी सम्पत्ति होने से हिमताजी को को-पार्सनरी सम्पत्ति भूमि में 1/6 हिस्सा रहा है एवं हिमताजी की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि को पार्सनरी सम्पत्ति का 1/6 हिस्सा हिमताजी के पुत्र नन्दकिशोर का रहा एवं नन्दकिशोर की मृत्यु के बाद इनके वारिस उत्तराधिकारी अप्रार्थीगण बहैसियत खातेदार राजस्व रेकार्ड में विधिवत दर्ज है, जो सही है।

3. कि प्रार्थीगण को राजस्व रेकार्ड की सम्पूर्ण जानकारी थी यह सही है कि नन्दकिशोर अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगाय 1/6 उसके वारिस है, जो सही है। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि पर पीहर सेवाडी आकर अपनी पैदावार का हिस्सा प्राप्त करती फल-फुट, सब्जिया प्राप्त करती का कथन गलत होने से अस्वीकार है। इस वर्ष रक्षाबन्धन पर प्रार्थीगण का सेवाडी आना वादग्रस्त भूमि पर जाने से रोका, पैदावार मूंग वगैरा नहीं देने की बात की इस पर प्रार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड की जांच की तो प्रार्थीगण को जानकारी हुई का तथ्य सरासर गलत होने से अस्वीकार है। आज से 54 वर्षों पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 नन्दकिशोर का बहैसियत को-पार्सनर भूमि का नियमानुसार 1/6 हिस्से का अकेले के नाम से राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज हुआ, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को हिमताजी की मृत्यु से थी। अप्रार्थी संख्या 1 नन्दकिशोर के जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि में 1/6 हिस्सा पर शान्तिपूर्वक एकमात्र कब्जा काश्त बहैसियत खातेदार काश्तकार नन्दकिशोर का ही रहा एवं पैदावार भी नन्दकिशोर ने ही प्राप्त की, नन्दकिशोर की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगाय 1/6 वादग्रस्त भूमि के 1/6 हिस्सा पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काविज है एवं पैदावार भी अप्रार्थीगण ने ही प्राप्त की है। शेष सभी तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि में खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश करने का कोई हक नहीं है, मात्र परेशान करने अप्रार्थीगण के खातेदारी हक हकूको पर कुठाराघात करने, क्षति कारित करने की नियत से वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसमें सफलता मिलने की तनिक भी उम्मीद नहीं है एवं वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्दर अवधिकाल नहीं होने से काबिल खारिज के है।
4. प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के अलावा अन्य खातेदारान को वाद एवं प्रार्थना-पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है, जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र कानूनन परितोषणीय नहीं है एवं प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की अपूरणीय क्षति होने वाली नहीं है, जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र काबिल खारिज के है।
5. कि प्रार्थीगण ने हिमताजी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान की विधिसंगत बतौर कायम मुकाम के नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज प्रार्थीगण की जानकारी होते हुये हुये अप्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदारान को तंग, परेशान करने के उद्देश्य से रेकार्ड्ड खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना एवं बिना बंटवाडा किये, बिना कब्जे के उक्त वाद एवं प्रार्थना-पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध गलतरूपेण पेश किया है। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है। सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है, जो कानूनन परिपोषणीय नहीं होने से प्रार्थीगण अप्रार्थीगण विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है।



अप्रार्थी संख्या 1/6 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपरिथत रहने से न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 /6 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अगल में लायी गई।

अप्रार्थी संख्या 1/6 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने तथा शेष अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत करने एवं अप्रार्थी संख्या 2 परोकार सरकार के विरुद्ध कोई अनुतोप नहीं होने से उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी की वादग्रस्त भूमि स्व. हिमताजी से प्राप्त होने से पुश्तैनी भूमि है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 आपस में भाई-बहन है। स्व. हिमताजी की मृत्यु होने पर वारिसान के तौर पर केवल एक पुत्र नन्दकिशोर के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया। स्व. हिमताजी ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयतनामा नहीं किया। निर्वसीयत एक हिन्दु पुरुष की मृत्यु होने पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पुत्र एवं पुत्रियों को समान हक अधिकार है, जिसके अनुसार हिमताजी के वारिसान में पुत्रियां प्रार्थीगण संख्या 1 लगाय 3 एवं पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 बहिस्ता बराबर के अधिकारी बनते हैं, परन्तु भूप्रबन्ध कार्यवाही के दौरान स्व. हिमता की मृत्यु के बाद दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण से अकेले नन्दकिशोर का नाम बतौर वारिस दर्ज कर दिया गया जो प्रारम्भ से ही शून्य है। उक्त त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण से प्रार्थीगण का हक अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। प्रार्थीगण स्व. हिमता के वादग्रस्त आराजी में निहित 1/6 हिस्ता में बहिस्ता बराबर की हकदार कानूनी रूप से है जिससे प्रार्थीगण द्वारा घोषणा खातेदारी का वाद एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जो वाद न्यायालय में विचाराधीन है तथा वाद प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के पक्ष में है। स्व. हिमताजी से प्राप्त वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि है तथा प्रार्थीगण स्व. हिमताजी के वारिसान होने से जन्म से ही वादग्रस्त आराजी में हक अधिकार निहित है। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध वाद के निस्तारण तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने एवं अप्रार्थीगण रिकार्ड में दर्ज त्रुटिपूर्ण इन्द्राज की आड में भूमि का अन्यत्र हस्तान्तरण नहीं करने इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में जारी किये जाने की दलील दी। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/4 की तरफ से दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये यह दलील दी गई की पुश्तैनी सम्पत्ति के मामले में यह मान्य धारणा है कि सभी वारिसान का अपने हिस्से तक कब्जा माना जावे चाहे रिकार्ड में नाम हो अथवा नहीं। विधवान वकील प्रार्थीगण श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा दौरान बहस अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न कानूनी उद्धरण पेश किये गये :-

1. RRT 2005(2) Mangeram vs Ratni Page 995 to 998
2. RRT 2009 (1) Makbool and ors. vs gani and ors. Page 141 to 145
3. RRT 2007 (2) Sanwarlal and ors. vs kisturmal and ors Page 813 to 816

अप्रार्थी संख्या संख्या 1/2, 1/3, 1/5 के अधिवक्ता श्री अय्यूब अली सैयद ने बहस में वकील प्रार्थी की दलीलों से सहमति जताते हुये प्रकरण में प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी। अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/4 के अधिवक्ता श्री भंवरसिंह राजपुरोहित ने वकील प्रार्थीगण की दलीलों का खण्डन करते हुये बहस में अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी की प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के अधिकार अभिलेखों में दर्ज रिकार्ड सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाकर त्रुटिपूर्ण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह कर एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञापति प्राप्त की है जो काबिल खारिज है। बहस में वकील अप्रार्थी द्वारा दलील दी की प्रार्थीगण के पिता हिमताजी की मृत्यु 56 वर्ष पूर्व हो चुकी है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2005 में पारित निर्णय से पुत्रियों को जो अधिकार दिये हैं वह भूतलक्षी नहीं होकर भविष्यलक्षी है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन वर्ष 2005 से पुत्रियों को अधिकार दिया गया है पहले नहीं जबकि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगणों द्वारा वर्ष 2005 से पूर्व की मृत्यु का उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है। 56 वर्ष की अवधि तक प्रार्थीगण ने कभी भी वादग्रस्त भूमि में अपने हक की मांग नहीं की एवं न ही दावा किया। अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/6 अधिकार अभिलेखों में रिकार्ड खातेदार है। रिकार्ड खातेदार होने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई आज्ञापति जारी नहीं की जा सकती है। अपनी दलीलों के समर्थन में RRT 2018(1) Pani bai vs Chandraprakash में पारित निर्णय की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया।

पेज लगातार—6

उप - खण्ड अधिकारी, वारी

राजस्थान विविध प्रकरण संख्या 1442/2018 अनवान अम्बादेवी वगैरा बनाम नन्दकिशोर के का.मु. धर्मेन्द्र कुमार वगैरा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संपादित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी

बादप्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कमी करवा नहीं रहा। स्व. हिन्दराजी की मृत्यु के पश्चात नन्दकिशोरजी का कब्जा काशत रहा तथा उसके बाद अधिकांक तक कब्जा अप्रार्थीगण का है प्रथम दृष्टया नाममा तथा सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में बनाया संचित है। हिन्दराजी की मृत्यु 1955 में हुई। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1955 की धारा 23 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार हिन्दराजी के वारिस के हतौर नन्दकिशोर का नाम अधिकार अभिलेखों में दर्ज हुआ तथा नन्दकिशोरजी की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थीगण का नाम अधिकार अभिलेखों में दर्ज हुआ तथा अप्रार्थीगण स्व. हिन्दराजी के बादप्रस्त भूमि में निहित 1/8 हिस्से की भूमि पर अपने जन्म से कब्जित है तथा विना नन्दकिशोर की मृत्यु के पश्चात अधिकार अभिलेखों में खातेदार दर्ज हुये है प्रार्थीगण अपने समुदाय रहती है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1955 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2005 में जो संशोधन किया गया है उस संशोधन से महिला को अपना पुरुषोत्तम हक पृथक करने का अधिकार वर्ष 2005 से पूर्व में प्रकरणों के लिये दिया गया है। जिससे प्रार्थीगण उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थायी आज्ञाएं जारी करने के अधिकारी नहीं होने से प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने की दलील दी। अपनी वसीलतों के समर्थन में निम्न कानूनी उद्धरण पेश किये :-

- 1- RRT 2018(1) Pani bai vs Chandraprakash Page 692 to 694-जिसके अनुसार प्रार्थी रिफॉर्मेड खातेदार है गोदपुत्र का प्रन वाद के विचारण में निर्मित किया जायेगा-निर्मित, प्रार्थी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार नहीं की जा सकती आदेश अमान्य।
- 2- RRT 2006(1) Bhanwarlal and ors. vs state of rajasthan and ors. page 545 to 548 - जिसके अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 व 224-परिसीमा अधिनियम 1983-धारा 6-खातेदारी अधिकारों की घोषणा व कब्रों के लिये वाद-वाद हेतु 10. 07.1959 को उत्पन्न हुआ-वादी के पिता व उनके भाईयों ने 12 वर्ष में वाद पेश नहीं किया-वाद पेश करने हेतु परिसीमा 12 वर्ष है-वाद हेतुक की दिनांक को वादी का जन्म नहीं हुआ था-वादी के पिता अथवा दादा ने 'एच' के खातेदार काश्तकार प्रोविडेंट की दिनांक को कोई उजर नहीं उठाया-निर्मित, परिसीमा काल बढ़ाया नहीं जा सकता तथा 1980 में पेश वाद कालवर्जित था तथा खारिज किया।
- 3- RRT 2016(1) prakash vs phulvanti and ors page 29 to 42 -जिसके अनुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956-धारा 6 (यथासंशोधित अधिनियम, 2005)-सम्पत्ति में पुत्रों का अधिकार-उच्च न्यायालय ने निर्मित किया कि संशोधन भूतलसी है और सम्बन्धित कार्यवाही पर लागू होता है-कानून स्पष्ट है कि संशोधन भविष्यलक्षी है-निर्मित, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्मित अपास्त किया और पुनः निर्णय हेतु नाममा उच्च न्यायालय को प्रतिरूपित किया।
- 4- RRT 2016(1) Vinay kumari chopra vs Sh. Vijay singh Page 499 to 508 -जिसके अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश 39 नियम 1 व 2- हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956-धारा 6(5)-सम्पत्ति में स्त्री का अधिकार-विभाजन हेतु वाद-अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना-पत्र विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया गया-सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर पूर्व में विभाजन होना साबित हुआ-20.12.2004 के पूर्व हुये विभाजन पर धारा 6(5) के प्रावधान लागू नहीं होते-हिन्दु अविभाजित परिवार की सम्पत्ति नहीं-आदेश न तो मनमाना है न प्रतिकूल-निर्मित, अपील न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप अस्वीकार किया गया।
- 5- RRT 2016(1) Biradhram vs pannaram Page 508 to 509
- 6- RRT 2005(1) Sarvati (Smt.) and Ors. vs Khemchand and Ors. Page 242 to 248 - जिसके अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955-धारा 88 व 188-द्वितीय अपील-पेश के स्थान पर एस.बी.एल के नाम भूमि दर्ज की-मृतक 'सी' भूमि का खातेदार था-सर्वा 2016-2019 व 2020 की जमाबंदी में प्रत्येक पुत्र के नाम 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज की-सर्वा 2032 की जमाबंदी में 'एस' के स्थान पर केवल 'के' का नाम दर्शाया-उसकी विधवा व पुत्री का नाम नहीं दर्शाया-विचारण न्यायालय ने वाद खिड़ी किया तथा सर्वोपम व 'के' को प्रत्येक के 1/3 हिस्से के साथ सह-काश्तकार घोषित किया-अपील में आदेश को संशुद्धि की-समवर्ती निष्कर्ष-भूमि संयुक्त खातेदारी में है-एक सह काश्तकार का कब्जा सभी का कब्जा है-हस्तक्षेप न्यायसंगत नहीं है।
- 7- RRT 2002(1) State of rajastha vs fularam and Ors. Page 365 369



Handwritten signature and text at the bottom right of the page.

117/11

**राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1442/2018 अनवान अम्बादेवी वगैरा बनाम नन्दकिशोर  
के का.मु. घमैन्द्र कुमार वगैरा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955  
सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी**

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं उभय पक्ष वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत प्रकरण में यह जाहिर है कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि स्व० हिमताजी से प्राप्त होने तथा हिन्दु उत्तराधिकारिता की वंश वृक्षावली के अनुसार प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में हक अधिकार होने से वर्तमान अधिकार अभिलेखों में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा में बहिरसा बराबर की खातेदारी घोषणा के साथ अप्रार्थीगण के विरुद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की मांग की हैं। तथा उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से पुश्तैनी को-पार्सनरी सम्पदा के हकूको की घोषणा हेतु प्रस्तुत वाद के निस्तारण तक अधिकार अभिलेखों में दर्ज अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगाय 1/6 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की जा रही हैं। इसके विपरित अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/4 का दावा है कि प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार नहीं है, राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज है, तथा मौके पर कब्जा भी अप्रार्थीगण का ही चला आ रहा है। प्रार्थीगण अपने ससुराल में रहती है। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला ही प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण खारिज किये जाने की मांग की जा रही हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 एवं दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 01 व 02 सी.पी.सी. में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु विधि द्वारा जो प्रावधान नियत किये गये हैं। उन प्रावधानों के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निर्णित करते समय न्यायालय को तीन बिन्दुओं- (1) प्रथम दृष्ट्या मामला बनना (2) सुविधा का संतुलन (3) अपुरणीय क्षति का मामला पर प्रकरण का परीक्षण करते हुये निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। जिससे हस्तगत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु विधि द्वारा स्थापित तीनो बिन्दुओं को निम्नानुसार निर्णित किया जाता है:-

**1. प्रथम दृष्ट्या मामला बनना:-**

प्रथम दृष्ट्या मामला बनने के परीक्षण का आधार रेकर्ड अथवा मौका स्थिति हो सकते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध सैटलमेंट पुर्व की जमाबंदी संवत् 2027 से 2030 में दर्ज इन्द्राज के अवलोकन से यह जाहिर है कि ग्राम सेवाडी के गत् खसरा नंबर 412 रकबा 43 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 412/2 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 567/1 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 570 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 570/1 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 412/1 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 564 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 568 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 569 रकबा 16 बिस्वा कुल खसरा-12 कुल रकबा 97 बीघा 15 बिस्वा सैटलमेंट पुर्व के अधिकार अभिलेखों में 1/6 हिस्सा में शंकर, छोगा व हिमता पि० प्रताप के नाम दर्ज थी। छोगाजी उर्फ अलकुजी व शंकरजी की मृत्यु ला औलाद होने से उनके जीवित भाई हिमताजी पुत्र प्रताजी के नाम दर्ज हुई तथा भूप्रबन्ध के बाद तैयार नये अधिकार अभिलेखों में ग्राम सेवाडी के पुराने खसरा नंबर 412 रकबा 43 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 412/2 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 567/1 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 570 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 570/1 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 412/1 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 564 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 568 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 569 रकबा 16 बिस्वा कुल खसरा-12 कुल रकबा 97 बीघा 15 बिस्वा के भू०भाग से कायम हाल खसरा नंबर 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447 रकबा क्रमशः 0.45 हैक्टर, 0.17 हैक्टर, 0.27 हैक्टर, 0.36 हैक्टर, 0.01 हैक्टर, 0.06 हैक्टर, 0.61 हैक्टर, 0.59 हैक्टर, 0.62 हैक्टर, 0.69 हैक्टर, 4.46 हैक्टर कुल खसरा-13 कुल रकबा 7.96 हैक्टर एवं दुसरा खाता जिसके खसरा नंबर 1993 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा एवं खसरा नंबर 1994 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गै.मु. सडा एवं तीसरा खाता जिसके खसरा नंबर 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 रकबा क्रमशः 0.43 हैक्टर, 0.26 हैक्टर, 0.38 हैक्टर, 0.35 हैक्टर, 0.36 हैक्टर, 0.27 हैक्टर, 0.25 हैक्टर, 0.46 हैक्टर, 0.50 हैक्टर, 0.15 हैक्टर, 0.30 हैक्टर, 0.20 हैक्टर, 0.70 हैक्टर, 0.28 हैक्टर, 0.81 हैक्टर, 0.36 हैक्टर, 0.41 हैक्टर, 0.43 हैक्टर, 0.17 हैक्टर, 0.14 हैक्टर, 0.23 हैक्टर, 0.26 हैक्टर कुल खसरा-22 कुल रकबा 7.70 हैक्टर इन तीनों खातों की भूमियों के 1/6 हिस्सा में शंकर, छोगा व हिमता पि. प्रताप की जगह नन्दकिशोर पुत्र हिमता दर्ज कर दिया गया।

पेज लगातार..08




*(Signature)*  
**39 - खण्ड अधिकारी, पाली**

जो इन्द्राज राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में ग्राम सेवाडी के खाता संख्या-942 में खसरा नंबर 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447 कुल खसरा-11 जुमले रकबा 7.89 हैक्टर में नन्द किशोर पुत्र हिमता 1/6 हिस्सा में अन्य सह खातेदारान् के साथ दर्ज हैं। इसी जमाबंदी पर लगे नोट के अनुसार म्यूटेशन संख्या 2700 दिनांक 2.10.2015 से विरासत के अनुसार नन्दकिशोर पुत्र हिमता के स्थान पर धर्मेन्द्र जितेन्द्रकुमार सुभाष दीपक रणजीत पुत्र नन्दकिशोर जशोदा पत्नि नन्दकिशोर का नाम दर्ज किया गया। इसी जमाबंदी पर लगे अन्य नोट के अनुसार म्यूटेशन संख्या 2745 दिनांक 29.2.16 (डिक्री बंटवारा) के अनुसार धर्मेन्द्र राकेश सुभाष दीपक रणजीत पि0 नन्दकिशोर जशोदा पत्नि नन्दकिशोर कौम रावल सा. देह खातेदार का खाता अलग करते हुये खसरा नंबर 1443 रकबा 0.60 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1447 रकबा 0.17 हैक्टर अप्रार्थीगण के बंट में रखा जाना प्रमाणित हैं। इसी प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 में दर्ज इन्द्राज के अवलोकन से यह जाहिर हैं कि ग्राम सेवाडी के खाता संख्या-171 में खसरा नंबर 1993, 1994 कुल खसरा-02 कुल रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गै.मु. वेरा व सडा में नन्दकिशोर पुत्र हिमता 1/6 हिस्सा में बतौर सह खातेदार दर्ज हैं। इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 में दर्ज इन्द्राज के अवलोकन से यह जाहिर हैं कि ग्राम सेवाडी के खाता संख्या-175 खसरा नंबर 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2004 कुल खसरा-22 जुमले रकबा 7.77 हैक्टर के 1/6 हिस्सा में बतौर सह खातेदार नन्द किशोर पुत्र हिमता दर्ज हैं। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदियों में दर्ज इन्द्राज के अनुसार वर्तमान में वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण रेकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण वर्तमान में रेकॉर्ड में खातेदार दर्ज नहीं है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में यह प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि सैटलमेंट पूर्व के अधिकार अभिलेखों में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या-01 के पूर्वज हिमताजी के नाम दर्ज थी। जो सैटलमेंट बाद के अधिकार अभिलेखों में अकेले अप्रार्थी संख्या-01 के नाम दर्ज कर दी गई। इस बिन्दु को लेकर दोनों पक्षों में कोई विरोध भी नहीं हैं, क्योंकि प्रार्थीगण स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में भूमि उनके पूर्वज हिमताजी के नाम बन्दोवस्त पूर्व के अधिकार अभिलेखों में दर्ज होने तथा उनके देहांत के बाद भू0प्रबन्ध कार्यवाही में अकेले नन्दकिशोर का नाम दर्ज कर दिया जाने से वादग्रस्त भूमि में हिन्दु उत्तराधिकारिता अधिनियम, 1956 के प्रावधानों अनुसार पुश्तैनी को-पार्सन्री सम्पदा में अपना हक होने से घोषणा खातेदारी का वाद एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया हैं। एवं प्रस्तुत वाद के निस्तारण में समय लगने से वादग्रस्त भूमि में अपना हक हिस्सा होने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की मांग की गई। एवं अप्रार्थीगण द्वारा हिमताजी की मृत्यु के बाद अप्रार्थी -01 नन्दकिशोर अकेले का नाम किये तथा इसकी जानकारी प्रार्थीगण को भलीभाँति हाने से एवं वर्तमान अधिकार अभिलेखों में भूमि में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं होने से अब 56 वर्ष की अवधि के बाद उक्त वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से प्रथम दृष्ट्या मामला ही प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनने की दलील दी। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के वर्तमान में रेकॉर्डेड खातेदार है। पुश्तैनी हक अनुसार प्रार्थीगण का हिस्सा बनता है अथवा नहीं ? इस बिन्दु का विनिश्चयन वाद के निर्णय पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में जबकि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि हैं, जिसमें भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान अकेले अप्रार्थीगण संख्या-01 के नाम दर्ज कर दी गई एवं प्रार्थीगण का नाम विलोपित कर दिया गया। जिसकी घोषणा खातेदारी के लिये वाद प्रस्तुत कर रखा है एवं वाद के साथ में उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। इस संबंध में विद्ववान् वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी उद्धरण RRT 2005(2) Mangeram vs Ratni Page 995 to 998 एवं RRT 2009 (1) Makbool and ors. vs gani and ors. Page 141 to 145 हस्तगत प्रकरण में सटीक हैं। RRT 2005(2) Mangeram vs Ratni Page 995 to 998 में माननीय राजस्व मंडल, अजमेर ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं कि यह प्रकरण विरासत से भूमि पर कब्जे व अधिकार से संबंधित हैं। विरासत से पूर्वज की भूमि पर स्वतः ही वारिसों का कब्जा माना जायेगा तथा इसके लिये वारिसों को कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहती हैं।

पेज लगातार.....09



  
उप - खण्ड अधिकारी, पाली

//9//

राजस्थान विविध प्रकरण संख्या 1442/2018 अनवान अम्बादेवी वगैरा बनाम नन्दकिशोर  
के का.मु. धमेन्द्र कुमार वगैरा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955  
सपटित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी

विवाद केवल माई-बहन के बीच हैं तथा उनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति पक्षकार नहीं हैं।  
ऐसी स्थिति में विवादित भूमि भले ही अप्रार्थी के खाते दर्ज हो गई हो परन्तु प्रथम दृष्ट्या  
प्रार्थीगण का भी हिस्सा अनुसार कब्जा होना प्रमाणित होता है। तथा प्रथम दृष्ट्या प्रकरण,  
सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में माने हैं। उक्त विवेचन से प्रथम  
2. सुविधा का संतुलन :-

प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में यह प्रमाणित है कि  
सैटलमेंट पूर्व के अधिकार अभिलेखों में वादग्रस्त भूमि हिमता पुत्र प्रतापजी के सह खातेदारी में  
दर्ज रही है। तथा भूप्रबन्ध के बाद तैयार मिसल बन्दोवस्त एवं उसके बाद तैयार अधिकार  
अभिलेखों रिकॉर्ड ऑफ साईटस जमाबंदियों में वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं कर  
अप्रार्थी संख्या 1/1 लगाय 1/6 के नाम दर्ज कर दिये गये हैं। वर्तमान अधिकार अभिलेखों में  
भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होने से प्रार्थीगण द्वारा पुश्तैनी भूमि में अपना हक होने से घोषणा  
खातेदारी का वाद एवं उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिस प्रार्थना पत्र  
पर न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2018 को प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध  
आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। एवं अब यदि उक्त प्रार्थना पत्र  
को खारिज कर दिया जाता है, तो अप्रार्थीगण द्वारा भूमि का अन्यत्र बेचान, हस्तान्तरण की  
समावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यदि अप्रार्थीगण रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राजो के अनुसार  
भूमि का किसी तीसरे पक्ष को बेचान, हस्तान्तरण करने में सफल हो जाते हैं, तो प्रार्थीगण द्वारा  
प्रस्तुत वाद एवं उक्त प्रार्थना पत्र का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। तथा प्रकरण में विभिन्न  
प्रकार की जटिलताएं बढ़ेगी तथा प्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी। इसके विपरीत यदि  
अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, तो अप्रार्थीगण के हितों पर कोई  
कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों कि वाद कार्यवाही में यदि शहादत इत्यादि के माध्यम से प्रार्थीगण का  
वाद साबित नहीं हुआ तो अप्रार्थीगण के अधिकार ज्यों के त्यों कायम रहेंगे। उक्त विवेचन से  
बिन्दु संख्या-02 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/4 के विरुद्ध निर्णित किया  
जाता है।

### 3. अपूर्णनीय क्षति का मामला :-

प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित होने  
से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने पर अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति  
होना संभाव्य नहीं है। इसके विपरीत यदि प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो अप्रार्थीगण  
संख्या 1/1 लगाय 1/6 जो कि वर्तमान अधिकार अभिलेखों में रिकॉर्डेड खातेदार है भूमि का  
बेचान हस्तान्तरण कर देंगे, जिससे मौके पर विवाद बढ़ेगा तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं  
उक्त प्रार्थना पत्र का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। उक्त विवेचन से बिन्दु संख्या-03 भी  
प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त न्यायिक नजीरो का ससम्मान अवलोकन किया  
जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरे : RRT 2018(1) Pani bai vs Chandraprakash  
Page 692 to 694, RRT 2006(1) Bhanwarlal and ors. vs state of rajasthan and ors. page 545 to 548  
RRT 2016(1) prakash vs phulvanti and ors page 29 to 42 उक्त प्रकरण में चरपा नहीं होती है  
होती है। वादी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरे 1.RRT 2005(2) Mangeram vs Ratni Page 995 to 998 ,RRT  
2009 (1) Makbool and ors. vs gani and ors. Page 141 to 145, RRT 2007 (2) Sanwarlal and ors. vs  
Kisturmal and ors Page 813 to 816 प्रार्थीगण के पक्ष में भलीभांती चरपा होती है।

निष्कर्षतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में यह सुस्पष्ट है कि वादीगण/प्रार्थीगण का  
वाद संवत् 2017 के अभिलेखों में पुर्वज हिम्मत के नाम दर्ज होने से पुश्तैनी को-पारसनरी  
हकूको का होने, एवं वर्तमान अधिकार अभिलेखों में अप्रार्थीगण का नाम त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज होने  
एवं अस्थाई आदेश के लिये आवश्यक तीन पूर्व शर्तों 1. प्रथम दृष्ट्या मामला, 2. सुविधा का  
संतुलन, 3. अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरो का  
पेज लगातार...10



39 - उ.प. अधिकारी, पाली

// 10 //

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1442/2018 अनवान अम्बादेवी वर्गेश बनाम नन्दकिशोर  
के का.मु. धमेन्द्र कुमार वर्गैरा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955  
सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी

प्रार्थीगण के पक्ष में हुबहु चस्पा होने से वादीगण/प्रार्थीगण का सरहद मौजा ग्राम सेवाडी तहसील बाली के हाल खसरा नंबर खसरा नंबर 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447 रकबा क्रमशः 0.45 हैक्टर, 0.17 हैक्टर, 0.27 हैक्टर, 0.36 हैक्टर, 0.01 हैक्टर, 0.06 हैक्टर, 0.61 हैक्टर, 0.59 हैक्टर, 0.62 हैक्टर, 0.69 हैक्टर, 4.46 हैक्टर कुल खसरा-13 कुल रकबा 7.96 हैक्टर एवं दूसरा खाता जिसके खसरा नंबर 1993 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा एवं खसरा नंबर 1994 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गै.मु. सडा एवं तीसरा खाता जिसके खसरा नंबर 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 रकबा क्रमशः 0.43 हैक्टर, 0.26 हैक्टर, 0.38 हैक्टर, 0.35 हैक्टर, 0.36 हैक्टर, 0.27 हैक्टर, 0.25 हैक्टर, 0.46 हैक्टर, 0.50 हैक्टर, 0.15 हैक्टर, 0.30 हैक्टर, 0.20 हैक्टर, 0.70 हैक्टर, 0.28 हैक्टर, 0.81 हैक्टर, 0.36 हैक्टर 0.41 हैक्टर, 0.43 हैक्टर, 0.17 हैक्टर, 0.14 हैक्टर, 0.23 हैक्टर, 0.26 हैक्टर कुल खसरा-22 कुल रकबा 7.70 हैक्टर इन तीनों खातों की भूमियों के 1/6 हिस्सा के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी. बाबत अस्थाई व्यादेश के संबंध में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2018 को पारित एक पक्षीय अंतरिम आदेश में किसी प्रकार की दखलन्दाजी उचित प्रतीत नहीं हैं। आदेश दिनांक 01.10.2018 को मूल वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर मूल राजस्व वाद सं० 49/2018 के संलग्न हो।

(डॉ. मास्कर बिश्नोई)

आर.ए.एस.

34 - सुपुंड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 28-5-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

34 - सुपुंड अधिकारी, बाली

